vinetur

शुल्क कटौती के बाद भारत के कुछ हिस्सों में स्कॉच व्हिस्की की कीमतें 10%-15% घटीं

U.K.-India समझौते में शुल्क 150% से 75% होने के बाद Diageo और Pernod Ricard ने चार राज्यों में कुछ Scotch लेबलों की कीमतें घटाईं।

बुधवार, 30 सितंबर 2026



U.K.-India व्यापार समझौते द्वारा British whisky पर आयात शुल्क घटाए जाने के बाद भारत के कुछ हिस्सों में Scotch whisky की कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को पहली स्पष्ट झलक मिली है कि टैरिफ बचत का एक हिस्सा स्टोर शेल्फ तक पहुंच रहा है।

The Economic Times में बुधवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, Diageo और Pernod Ricard ने भारत के कई राज्यों में कुछ Scotch लेबलों की कीमतें लगभग 10%-15% घटाई हैं। ये कटौतियां महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और उत्तर प्रदेश में देखी गई हैं, जहां Johnnie Walker Black Label और J&B जैसे उत्पादों की खुदरा कीमतें नीचे आई हैं। स्थानीय कीमतों में संशोधन राज्य-स्तरीय मंजूरी प्रणालियों, वितरण चैनलों और खुदरा स्टॉक में आगे बढ़ते रहने के साथ इन कटौतियों के और राज्यों में फैलने की उम्मीद है।

इन मूल्य परिवर्तनों की पृष्ठभूमि 15 जुलाई को U.K.-India व्यापार समझौते के लागू होने से जुड़ी है, जिसने British whisky पर भारत का टैरिफ 150% से घटाकर 75% कर दिया, ब्रिटिश सरकार के व्यापार विभाग के अनुसार। इसका मतलब 75 प्रतिशत अंकों की कटौती, या 50% की सापेक्ष कमी है। समझौते के तहत, अगले 10 वर्षों में शुल्क के और घटकर 40% होने की योजना है।

भारतीय बाजार के लिए कम टैरिफ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयातित Scotch लंबे समय से घरेलू रूप से उत्पादित व्हिस्की की तुलना में भारी कीमत-हानि झेलता रहा है। खुदरा मार्जिन और राज्य कर जोड़ने से पहले भी, पुराना आयात शुल्क British ब्रांड्स की लैंडेड कॉस्ट को तेज़ी से बढ़ा देता था। उद्योग अधिकारियों और विश्लेषकों ने महीनों से कहा है कि यह समझौता भारत में आयातित स्पिरिट्स तक पहुंच बढ़ा सकता है, लेकिन उपभोक्ता स्तर पर इसके प्रमाण अब तक सीमित थे।

भारत मात्रा के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा व्हिस्की बाजार है, इसलिए Scotch की कीमतों में किसी भी बदलाव पर उत्पादकों, वितरकों और निवेशकों की करीबी नजर रहती है। आयातित Scotch और स्थानीय व्हिस्की के बीच कम हुआ मूल्य-अंतर अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को नए उपभोक्ता जोड़ने में मदद कर सकता है, खासकर शहरी बाजारों में जहां प्रीमियम और सेमी-प्रीमियम श्रेणियां बढ़ रही हैं। Diageo और Pernod Ricard जैसी वैश्विक कंपनियों के लिए, भारत जैसे बड़े बाजार में मामूली मूल्य कटौती का भी अहम असर हो सकता है।

साथ ही, शुरुआती कटौतियों को राष्ट्रीय मानक नहीं माना जाना चाहिए। भारत में व्हिस्की के लिए कोई एक समान देशव्यापी खुदरा कीमत नहीं है। शराब की कीमतें राज्य-दर-राज्य आबकारी शुल्क, स्थानीय लेवी, पंजीकरण शुल्क, लेबल मंजूरियों, वितरण लागत और खुदरा मार्जिन के जरिए तय होती हैं। इस व्यवस्था के कारण, एक ही बोतल की कीमत राज्य की सीमाओं के पार अलग-अलग हो सकती है, और आयात शुल्क में बदलाव समान रूप से या तुरंत प्रभाव नहीं डालते।

रिपोर्ट में उद्धृत 10%-15% की गिरावट महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापक बाजार के पैमाने के लिए अभी भी अपूर्ण है। यह आंकड़ा एक द्वितीयक स्रोत से आया है और देशव्यापी भारित औसत का प्रतिनिधित्व नहीं करता। रिपोर्ट के साथ Scotch के लिए कोई आधिकारिक अखिल-भारत खुदरा मूल्य श्रृंखला प्रकाशित नहीं की गई, और अभी तक बिक्री मात्रा, राजस्व वृद्धि या बाजार हिस्सेदारी में बदलाव के बाद के आंकड़े भी नहीं हैं, जो दिखा सकें कि उपभोक्ता कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

भारत के शराब बाजार की संरचना का मतलब यह भी है कि कंपनियां टैरिफ लाभ का केवल एक हिस्सा आगे बढ़ाने का विकल्प चुन सकती हैं। आयातक और ब्रांड मालिक कम शुल्क का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं: शेल्फ कीमतें घटाकर बिक्री मात्रा बढ़ाना, उच्च-कर वाले राज्यों में मार्जिन बचाना, प्रचार-खर्च के लिए फंड देना, या उत्पाद मिश्रण को अधिक मूल्यवान लेबलों की ओर समायोजित करना। राज्य सरकारें स्थानीय कर नीति या प्रशासनिक देरी के जरिए अंतिम नतीजे को भी प्रभावित कर सकती हैं। कुछ मामलों में, वह पुराना स्टॉक जो टैरिफ कटौती से पहले बाजार में आया था, नई खेपों के कम दामों पर आने से पहले भी पहले वाली कीमतों पर बेचा जा सकता है।

Scotch उत्पादकों के लिए, भारत को लंबे समय से सबसे आशाजनक विकास बाजारों में से एक माना गया है, लेकिन टैरिफ और विनियमन के कारण बड़े पैमाने पर प्रवेश करना भी सबसे कठिन रहा है। 75% तक की कटौती इन बाधाओं को खत्म नहीं करती, लेकिन देश में आयातित व्हिस्की बेचने की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है। अगले दशक में 40% तक का आगे का क्रमिक रास्ता अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को मूल्य निर्धारण, विपणन और वितरण रणनीतियों की बेहतर निश्चितता के साथ योजना बनाने के लिए अधिक गुंजाइश देता है।

आगे क्या होता है, यह इस पर निर्भर करेगा कि मौजूदा मूल्य कटौतियां कितने व्यापक रूप से फैलती हैं और क्या उपभोक्ता इतनी संख्या में प्रतिक्रिया देते हैं कि खरीद पैटर्न बदल सकें। आने वाले महीनों में अधिक राज्यों में खुदरा कीमतों पर करीबी नजर रहेगी, खासकर बड़े उपभोग बाजारों में, जहां Scotch परंपरागत रूप से उच्च-आय वाले पीने वालों तक सीमित रहा है। फिलहाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा और उत्तर प्रदेश में की गई कटौतियां अब तक का सबसे

स्पष्ट संकेत हैं कि यह व्यापार समझौता भारत के उपभोक्ताओं द्वारा आयातित British whisky के लिए चुकाई जाने वाली कीमतों को प्रभावित करना शुरू कर रहा है।